भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 802

09 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डाटाबेस

802. श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त डाटाबेस से सहकारी समितियों को क्या लाभ होगा; और

(ग) यह डाटाबेस कब तक बन जाने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग) सरकार सहकारी समितियों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करने की योजना बना रही है और तदनुसार हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अंतर्गत विविध डाटा सेट, कई राज्य विशिष्ट कानूनों और विभिन्न योजनाओं वाली लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो इस परियोजना के लिए एक बड़ी चुनौती है। सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डाटाबेस, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संघों, कोऑपरेटर्स और क्षेत्रीय संस्थानों जैसे नाबार्ड आदि के लिए मुख्य योजना उपकरण के रूप में कार्य करेगा।

******